



सत्यमेव जयते

एनआईसी तेलंगाना: ** तेलंगाना राज्य न्यायिक अकादमी (टीएसजेए) में तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए एनआईसी तेलंगाना अधिकारियों द्वारा कार्यशाला **

तेलंगाना राज्य उच्च न्यायालय रजिस्ट्री स्टाफ के लिए उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित तेलंगाना राज्य न्यायिक अकादमी, हैदराबाद में 20 दिसंबर 2025 को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। तेलंगाना उच्च न्यायालय के तकनीकी कर्मचारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

प्रशिक्षण का आयोजन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), तेलंगाना के अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय के अनुरोध पर माननीय ई-कमेटी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार चल रहे "ईकोर्ट्स क्षमता निर्माण कार्यक्रम" के तहत टीएसजेए के समन्वय में किया गया।

सत्र का उद्देश्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रखरखाव, डेटा प्रतिकृति और निगरानी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण और लैन कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में प्रतिभागियों की समझ को बढ़ाना था और उच्च न्यायालय के मुख्य अनुप्रयोगों जैसे ईसीआईएस, ईफाइलिंग और ईपे की झलक मिली।

निम्नलिखित एनआईसी तेलंगाना अधिकारियों ने सत्रों का नेतृत्व किया और अपने-अपने विषयों पर प्रस्तुतियां दीं:

1. **श्री जी. अप्पी रेड्डी, निदेशक (आईटी)**
कार्यक्रम का अभिविन्यास और अवलोकन, सॉफ्टवेयर प्रबंधन - ईसीआईएस, ईफाइलिंग और ईपेमेंट
2. **सुश्री श्रीलता गोरला, संयुक्त निदेशक (आईटी)**
साइबर सुरक्षा - साइबरस्पेस में कार्य और नेटवर्किंग की मूल बातें
3. **श्री शिव रामुलु, वरिष्ठ निदेशक (आईटी)**
हार्डवेयर प्रबंधन और रखरखाव - कंप्यूटर अवसंरचना का अवलोकन
4. **श्री के.वी. सूर्य नारायण, उप निदेशक (आईटी)**
हार्डवेयर प्रबंधन और रखरखाव - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और हाइब्रिड सुनवाई
5. **श्री विनोद कुमार, सहायक निदेशक (आईटी)**
सर्वर और नेटवर्क प्रशासन
6. **श्री सनापाला चिरंजीवी, सहायक निदेशक (आईटी)**
डेटा प्रबंधन



बाएँ से दाएँ

1. श्री विनोद कुमार, सहायक निदेशक (आईटी)
2. श्री सनापाला चिरंजीवी, सहायक निदेशक (आईटी)
3. श्री जी. अप्पी रेड्डी, निदेशक (आईटी)
4. श्री शिव रामुलु, वरिष्ठ निदेशक (आईटी)
5. सुश्री श्रीलता गोरला, संयुक्त निदेशक (आईटी)



प्रशिक्षण कार्यक्रम की झलकियाँ





कार्यशाला ज्ञान साझा करने और व्यावहारिक शिक्षा के लिए एक मूल्यवान मंच के रूप में काम करती है, जिससे प्रतिभागियों को अपनी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने और पूरे राज्य में ई-कोर्ट्स बुनियादी ढांचे के सुचारू संचालन का समर्थन करने में मदद मिलती है।
